आओ मिल कर

फासीवादी दमन के खिलाफ अखिल भारतीय अधिवेशन

सफल बनाएं

21 व 22 फरवरी 2019

स्थानः प्यारे लाल भवन, आयकर भवन के समीप, नई दिल्ली

उद्घाटन सत्र

21 फरवरी 2019, प्रातः 11 बजे

प्रमुख वक्ता

न्यायमूर्ति (से०नि) जनार्दन सहाय

विशेष अतिथि

अरुंधति रॉय

हम भी देखेंगे
जब जुल्मो-सितम के कोह-ए-गरां
रूई की तरह उड़ जायेंगे

तानाशाही का विरोध करतीं फैज़ अहमद फैज़ की लोकप्रिय नज्म 'हम देखेंगे' की ये पंक्तियाँ हमारे देश के मौजूदा हालात में बड़ी अहमियत रखती हैं। जिस तरह सत्ता में बैठे और सत्ता के करीबी ताकतवर लोगों का जनता पर नाना प्रकार से हमला बढ़ा है उसे सिर्फ फासीवाद के रूप में ही समझा जा सकता है। 'फासीवाद' का जिक्र होते ही दिमाग में मुसोलिनी और हिटलर की तस्वीर उभरती है। यह सच ही है कि ये फासीवादी नेता हमारे देश के शक्तिशाली दमनकारी लोगों के नायक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिष्ठापक नेता हेडगेवार के गुरु कहे जाने वाले बालकृष्ण मूंजे जिन्होंने सन 1931 में रोम जा कर उन संस्थानों का मुआयना किया था जो लोगों में फास. ीवादी सोच का प्रसार कर रहे थे और उन्हें फौजी शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने मुसोलिनी की इटली के बारे में अपने दैनिकी में लिखा था कि, "फासीवादी सोच लोगों में एकता की भावना का विकास करने में सहायक होती है.... भारत और खास कर हिन्दू भारत को ऐसे फौजी संस्थानों की जरूरत है जो युद्ध स्तर पर हिन्दुओं और उनकी सोच का शुद्धिकरण कर सके।" गोलवरकर के उत्तराधिकारी हेडगेवार ने अपनी किताब 'बंच ऑफ थॉट्स' में मुसलमानों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों को तीन आतंरिक खतरों के रूप में दर्शाया है।

केंद्र शासित भाजपा सरकार के राज में इन ताकतों द्वारा दलितों, अल्पसंख्यकों और युक्तिवादी लोगों पर होने वाले हमले न तो अकस्मात् हो रहे हैं ना ही इनमें अचानक कोई वृद्धि हुई है बल्कि ये हमले पूरी तरह से सोचे-समझे और योजनाबद्ध तरीके से किये जा रहे हैं जो कि संघ की हिंदुत्ववादी सोच और भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की नीति पर आधारित हैं। 15 सितम्बर 2015 को दादरी, उत्तरप्रदेश में भीड़तंत्र ने अखलाक़ को गाय का मांस रखने के अपराध में मौत के घाट उतार दिया। मार्च 2016 में मस्तान अब्बास को हरियाणा में मवेशियों का व्यापार करने के अपराध में जान से मार दिया गया, उसी महीने झारखण्ड के लातेहार में मवेशियों का व्यापार करने वाले दो लोगों को मार डाला गया, एक 13 साल के बच्चे की लाश पेड़ से टंगी मिली। 1 अप्रैल 2017 को अलवर, राजस्थान में पहलू खान को पीट-पीट कर मार डाला गया और एक साल बाद 18 जुलाई को रकबर खान का भी यही हश्र हुआ। 10 जनवरी 2018 को कठुआ, जम्मू में 8 साल की बच्ची आसिफा बानो का अपहरण हुआ और उसके बाद मंदिर परिसर में उसका नृशंस बलात्कार किया गया। ये हत्याएं तथाकथित गौरक्षकों और संघ परिवार और उससे सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं का संरक्षण पा रहे गुंडों ने की है। गुजरात के ऊना में जिस तरह 7 दलित युवकों को मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने के अरोप में सवर्णों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया उससे हिंदुत्ववादी ताकतों का भयानक सच सामने आ चुका है। जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में दलितों पर हुए हमले ने सवर्णों की पक्षधर और दलितों की आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकने वाली भाजपा सरकार की असलियत लोगों के सामने रख दी है। नरेंद्र दभोलकर, गोविन्द पंसारे, एम.एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश जैसे तर्कवादी लोगों की हत्या इस बात की साक्षी है कि भाजपा सरकार को वैसे लोग बर्दाश्त नहीं जो उसके हिंदुत्व प्रयोजन की आलोचना करते हों। वर्षों के संघर्ष के बाद महिलाओं ने जो अधिकार पाए हैं उन्हें भी कुचला जा रहा है। संघ की मंशा के अनुसार महिलाओं को मनुवादी खाके में कैद करने की तैयारी है जहाँ महिलाओं को हमेशा ही दोयम दर्जा मिलता है। इस नीति का जो भी विरोध करता है हिंदुत्ववादी ताकतें उन पर हमला करती हैं। सबरीमला मामला इसी पितृसत्तात्मक सोच और उसके तहत महिलाओं के अधिकारों पर हमले का द्योतक है। आदिवासियों को न सिर्फ उनके जमीन से बेदखल किया जा रहा है वरन उनकी भिन्न और स्वतंत्र संस्कृतिक पहचान मिटा कर उन्हें हिन्दू बनाने की कवायद ज़ोरों से चल रही है।

अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में इस सरकार ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम का भगवाकरण मात्र किया है। ऐसा करने के लिए इसने हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले अपनी पिठ्ठुओं को इन संस्थानों के वरिष्ठ पदों पर काबिज किया है। विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्थान और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक और सी.बी.आई भी इससे अछूते नहीं हैं। मीडिया और विधिक महकमों को मातहत करने के लिए या तो डराया जाता है

या तोहफे दे कर लुभाया जाता है। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में हैं और प्रतिरोध के स्वर दबाये जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारों की पैरोकारी करने वाले लोगों को 'शहरी माओवादी' (अर्बन माओइस्ट) कह कर आतंकित किया जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले में हुई गिरफ्तातरियाँ इसका ताजा उदाहरण हैं। जो भी संघ की इस हिंदुत्ववादी एकल और समरूपी संस्कृति का विरोध करता है उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है और संघी गुंडों को भारत माता के नाम पर हमला करने का लाइसेंस मिल जाता है।

यह सब एक ऐसे दौर में हो रहा है जब देश के ग्रामीण क्षेत्र और खास कर किसान एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। संघ निर्देशित भाजपा सरकार विदेशी निवेश और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए व्यापार करने में आसानी (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) का पुरजोर समर्थन कर रही है और इसके लिए मेहनतकश वर्ग द्वारा संघर्ष कर हासिल की गयी सभी अधिकारों की बलि चढाने के लिए तत्पर है। साथ ही बाजार में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेल और रक्षा के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश करने की स्वीकृति दे दी है। अंबानी, अडानी और मोदी सरीखे घरानों को लुभाने के लिए मोदी-शाह की यह सरकार उनकी गुलामी करने के लिए तैयार है। एन.एस.एस.ओ द्वारा जारी किये गए हालिया आंकड़ों से उजागर हुआ है कि देश में बेरोजगारी की दर 6.7% हो चुकी है और अपने चरम पर है। कहा जा रहा है की देश में नोटबंदी के कारण 1 करोड़ से भी अधिक नौकरियों का नुक्सान हुआ है। सरकार किसके भले की सोच सोच रही है यह तो इसी बात से साफ है कि अंतरिम बजट में गोकुल मिशन के तहत गौ सेवा के लिए 750 करोड़ और खून-पसीना बहा रहे 40 करोड़ से भी अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मात्र 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

सरकारी दमन की परवाह न करते हुए जनता ने भाजपा-संघ के फासीवादी हमले का विरोध किया है। जे.एन.यु, जादवपुर, हैदराबाद, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और टी.आय.एस.एस आदि के क्षेत्रों का विरोध, ऊना मामले और अनुसूचित जाती और जनजाति अधिनियम को कमजोर किये जाने के विरोध में देश भर में दलितों का प्रदर्शन, पथलगढ़ी आंदोलन और वैज्ञानिकों, पत्रकारों, लेखकों, कवियों और सामजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हुए स्वतंत्र आंदोलन जैसे की 'नॉट इन माई नेम', 'किस किस को कैद करोगे', 'मैं भी अर्बन नक्सल' आदि का भी उदय हुआ है। संघ परिवार की हिंदूवादी हमले का विरोध कर रही इन सभी शक्तियों को सम्मिल्लित कर एक साथ एक मंच पर लाने की मंशा से विभिन्न जन आन्दोलन साथ मिल कर 21–22 फरवरी 2019 को दिल्ली में फासीवाद के खिलाफ अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। अधिवेशन की आयोजक समिति सभी जनतांत्रिक और लोकतंत्र प्रेमी लोगों से आवाह्न करती है कि वे इस अधिवेशन को सफल बनाने में साथ दें।

कार्यक्रम

21 फरवरी 2019	
उद्घाटन सत्र *न्यायमूर्ति (से०नि) जनार्दन सहाय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)*	*प्रातः* *11–12:30 बजे*
विशेष अतिथि *अरुंधति रॉय*	
फासीवादी हमला और आर्थिक परिवेश *वक्ताः एन. वेणुगोपाल*	*अपराहन* *12:30–1 बजे*
शिक्षा का भगवाकरण *वक्ताः निवेदिता मेनन, पी.एस.यू , बासो, बी.सी.एम(बी.एच.यू)*	*अपराहन* *2–4 बजे*
महिलाओं पर हमले *उमा चक्रवर्ती*	*अपराहन* *4–5:30 बजे*
अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर हमले *वक्ताः जसपाल सिंह सिद्धु, सोनी सोरी, दामोदर तूरी*	*अपराहन* *5:30–7 बजे*
22 फरवरी 2019	
दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले *वक्ताः मसीहुद्दीन संजरी, कँवल भारती, प्रो.बिस्वजीत चक्रवर्ति*	*प्रातः* *9–10:30 बजे*
मीडिया पर फासीवादी हमला *वक्ताः सईद नकवी, सिद्धार्थ वर्धराजन, अनिल चमड़िया*	*प्रातः* *10:30–11:30 बजे*
हिंदूत्व फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर *वक्ताः विभिन्न संगठन*	*प्रातः* *11:30–1 बजे*
हिंदूत्व फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर *वक्ताः विभिन्न संगठन*	*अपराहन* *2–4 बजे*

आयोजक समिति
फासीवादी दमन के खिलाफ
अखिल भारतीय अधिवेशन